

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 01 जनवरी, 2010

विषय: आगामी कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, मंगलौर के क्षेत्रान्तर्गत आन्तरिक सड़कों के सुधार एवं सैन्दर्यीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 811/कु.मे./III(191)/न.प.प.मंग. दिनांक 1.08.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर (हरिद्वार) द्वारा संलग्न सूची में अंकित कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 39.67 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 39.30 लाख (रु. उन्तालीस लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी दशा में कार्यों की जुल्मीकेसी न हो तथा कार्य की आवश्यकतानुसार ही सड़कों को निर्मित किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निर्माण कार्यों को यथा आवश्यकता अनुमन्य कार्यदायी संस्थाओं से कराया जाए एवं गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी पर्यवेक्षण व अनुश्रवण की स्वतंत्र व्यवस्था की जाए।
2. आन्तरिक सड़कों में जहां पर जल निगम/जल संस्थान/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई आदि द्वारा पाइप लाइनों अथवा सीवर बिछाने अथवा टेलीफोन लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया हो, वहीं पर सड़कों का निर्माण किया जाए। जिन सड़कों पर किसी कार्यदायी संस्था के निर्माण कार्य हेतु खुदाई का कार्य होना शेष हो, वहां तत्परचात ही सड़क बनाने का कार्य किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथा आवश्यकता दो किशतों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किशत का कोषागार से आहरण किया जाएगा। उक्त धनराशि कोषागार से आहरित करके निकाय द्वारा अपने पी.एल.ए. खाते में रखी जायेगी और इसका उक्त खाते से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 'थर्ड पार्टी चैकिंग' की व्यवस्था भी की जायेगी और उक्त तृतीय पक्ष से चैकिंग की रिपोर्ट शासन को भी समय-समय पर दी जायेगी। उक्त पर होने वाला व्यय उक्त अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. उक्त कार्यों को इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा एवं आगणनों का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्माण कार्य तथा इस हेतु निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
11. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
12. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि मेलावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तब समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
14. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
15. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
16. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
17. कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं सम्बन्धित निर्माण एजेंन्सी पूर्णतया उत्तरदायी माने जायेंगे।
18. अकुशल एवं कुशल श्रमिकों तथा अन्य नियोजित दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य मजदूरी ही भुगतान की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या-1614/IV(1)/2009- 39(साम0)2006-टी0सी0 दिनांक 24.11.2009 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रु0 100.00 करोड़ के सापेक्ष आहरित किया जायेगा तब पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखशीर्षक में किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 129/XXVII(2)/2009 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 918 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक 01/01/2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पीड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर (हरिद्वार)।
12. गार्ड बुक।

अज्ञा से,
(सुभाष चन्द)